डुमरा, बिहार तक रेलवे सर्वेक्षण का पूरा किया जाना

7864. **श्री जनार्दन यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित मंदार-हिल के डुमरा तक विस्तारण कार्य के सर्वेक्षण को पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो शेष कार्य को कब तक पूरा किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ): (क) जी हां।

(ख) परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेज दी गयी है। योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

मध्य प्रदेश में रेल लाइनों का बिछाया जाना

7865. **श्री गोविन्द राम मिरी:** क्या रेल मंत्री 11 मई 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 6832 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नई रेल लाइनें बिछाने के संबंध में सर्वेक्षण कब किया गया था तथा इस सर्वेक्षण की अवधि क्या थी;

(ख) क्या बिलासपुर से मध्य प्रदेश तक रेल लाइन बिछाने के संबंध में सर्वेक्षण किया गया था यदि हां तो यह सर्वेक्षण कब किया गया था और उस सर्वेक्षण के क्या नतीजे निकले और उसके अभी तक भी कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) दिल्ली-राजहरा-जगदलपुर लाइन के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव को योजना-आयोग के पास कब भेजा गया और इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है और निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ): (क) ढल्लीराजहरा से जगदलपुर तक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण 1987 में किया गया था।

(ख) बिलासपुर-जबलपुर लाइन का सर्वेक्षण 91-92 में किया गया था। सर्वेक्षण से पता चला कि 372 कि०मी० लंबी लाइन की लागत 392 करोड़ रुपये आयेगी और प्रतिफल की दर नकारात्मक होगी। परियोजना अलाभप्रद प्रकृति की होने तथा संसाधनों की भारी तंगी को ध्यान में रखते हुए परियोजना के अनुमोदन पर विचार नहीं किया जा सका।

(ग) ढल्लीराजहरा-जगदलपुर लाइन का निर्माण शुरू करने के लिए एक योजना आयोग के अनुमोदन के लिए 11.11.93 को भेजी गयी थी। निर्माण कार्य का पूरा होना योजना आयोग का अनुमोदन और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रेलगाड़ियां चलाने में निजी क्षेत्र की सहभागिता

7866. **श्री गोविन्द राम मिरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय ने निजी क्षेत्र को कुछ गाड़ियों को चलाने का उत्तरदायित्व सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है और इस निर्णय के संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रेल मंत्रालय ने विश्राम गृह और कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण के ठेकों को भी निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है और इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने संलग्न विवरण **(नीचे देखिये)** में दिए गए बड़ी लाइन के 5 सर्किटों पर पर्यटक गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन और प्रबंधन के लिए बोलियां सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों से आमंत्रित की हैं ऐसा अवसंरचना में निवेश आकर्षिक करने की सरकार की नई आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा इसका उद्देश्य देश में पर्यटक यातायात में वृद्धि करना और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित करना है।

(ग) जी नहीं।